बैंकों की मदद से ओडीओपी सेक्टर होगा मजबूत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष के साथ प्रमुख सचिव एमएसएमई ने की चर्चा

लखनऊ। प्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) सेक्टर को बैंकों की मदद से मजबूती दी जाएगी। इसके लिए ओडीओपी परियोजनाओं को बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में मजबूती से स्थापित करने की रणनीति बनाई गई है। शासन ने बैंकों से परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों के ऋण आवेदनों को जल्द मंजूरी दिलाने को कहा है।

एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने गुरुवार को यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी व सीईओ तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष पीएस जय कुमार के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल ओडीओपी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने की तैयारी है। विभाग ने पहल करते हुए लीड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से ओडीओपी व एमएसएमई इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहायता दिलाने का अनुरोध किया है। नवनीत सहगल ने कहा कि बैंकों में ऋण के लिए 17000 हजार से ज्यादा आवेदन हैं, लेकनि अब तक सिर्फ 719 को ही मंजूरी मिल पाई है। ब्यूरो

मदद के लिए आगे आएं बैंक

प्रमुख सचिव ने बैंकर्स समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि ओडीओपी के तहत ऋण आवेदन करने वाली इकाइयों को आसानी से वित्तपोषण की व्यवस्था कराएं ताकि वे मजबूती से बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। ओडीओपी उत्पादों की मार्केटिंग व ब्रांडिंग के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ऐसे में बैंकों को भी इसमें मदद के लिए आगे आना चाहिए।

एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष पीएस जय कुमार से मुलाकात की।

एनपीए खत्म करने के लिए एकमुश्त समाधान जरूरी

सार्वजनिक बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) को खत्म करने के लिए एकमुश्त समाधान जैसी योजनाएं प्रभावी हो सकती हैं। इसके चलते विभूतिखंड स्थित अंचल कार्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी व सीईओ पीएस जयकुमार ने एकमुश्त समाधान के तहत ऋण मुक्ति शिविर में लोन लेने वाले ग्राहकों को स्वीकृति पत्र दिए। वे लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की समीक्षा बैठक में भाग लेने आए हैं। अंचल प्रमुख रामजस यादव ने बताया कि लखनऊ क्षेत्र के 2205 एनपीए खातों में 8.17 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के समझौता प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

Amar Ujala Page No-4 (23/08/2019)